"दो महासागरों का संगम"

भारतीय गणराज्य की संसद में
जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिनज़ो आबे का अभिभाषण
22 अगस्त, 2007

राज्य सभा के सभापति महामहिम उप राष्ट्रपति (मोहम्मद हामिद अंसारी),
महामहिम प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह,
लोक सभा अध्यक्ष महामहिम श्री सोमनाथ चटर्जी,
भारत की जनता के माननीय संसदीय प्रतिनिधिगण,
मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य
महामहिम राजदूत, भाइयो और बहनो,

मैं आज अपना संबोधन शुरू करने से पहले भारत में प्रकृति के प्रकोप का शिकार हुए लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूँ जिन्हें, हाल में आई बाढ़ से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, विशेषकर बिहार के लोगों को, जो इस समय भी भारी मुश्किलों से जूझ रहे हैं।

आज मुझे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्तिशाली सत्ता के इस मंदिर को संबोधित करने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज यहाँ एशिया के एक अन्य लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की ओर से आपसे जापान और भारत के भविष्य पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आया हूँ।

The different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea.

"भले ही अलग–अलग धाराओं के स्रोत विभिन्न स्थानों से निकलते हों लेकिन उन सभी का पानी समुद्र में ही मिलता है।"

आज मुझे महान आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानन्द, जो भारत की विश्व को एक महान देन है, के इन शब्दों के साथ अपना संबोधन प्रारंभ करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है।

मित्रो, आज वास्तव में हम ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से कहाँ खड़े हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं 1655 में मुगल शहज़ादा दारा शिकोह द्वारा रचित पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करना चाहूँगा।

आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ *दो महासागरों का संगम* हो रहा है।

प्रशांत और हिन्द महासागर आज एक स्वतंत्र और समृद्ध सागर के रूप में एक गतिशील संयोजन उत्पन्न कर रहे हैं। इस "विशाल एशिया" ने भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है और अब इसने एक विशिष्ट रूप लेना शुरू कर दिया है। यह हमारे दो देश ही हैं जिनमें यह सुनिश्चित करने की योग्यता – तथा दायित्व है। हम जितना ही इन सागरों को पोषित और समृद्ध करेंगे, ये हर दृष्टि से उतना ही अधिक पारदर्शी सागर बनकर विशाल रूप धारण करेंगे।

मैं आज यहाँ आपके माध्यम से भारत की एक अरब जनसंख्या को सीधे यह संदेश देने आया हूँ, और इसीलिए मैं आज आपके समक्ष संसद के इस केन्द्रीय कक्ष में भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बात कर रहा हूँ।

* *

इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब जापान और भारत ने एक–दूसरे को आकर्षित और प्रभावित किया है।

विवेकानंद ने तेनशिन ओकाकुरा से मित्रता की, जिनकी विचारधारा आधुनिक जापान के उस शुरुआती काल से अधिक परिपक्व थी और वे एक तरह से नवचेतन युग के प्रतिपादक थे। ओकाकुरा को न केवल विवेकानंद से मार्गदर्शन मिला, बल्कि उन्हें विवेकानंद की सच्ची शिष्या और विख्यात महिला समाज सुधारक बहन निवेदिता का सान्निध्य भी प्राप्त हुआ था।

कल मैं प्रातः कोलकाता के लिए रवाना हो जाऊँगा, जहाँ मैं संभवतः न्यायमूर्ति राधाबिनोद पाल के पुत्र से मुलाकात करूंगा। न्यायमूर्ति पाल का सुदूर पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायालय के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने के लिए आज भी अनेक जापानियों द्वारा अत्यधिक सम्मान और आदर किया जाता है।

बंगाल प्रांत के लोग, जिन्होंने जापान के साथ रिश्ता कायम किया था – चाहे उस व्यक्ति से जिसके नाम पर आज कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है (सुभाष चंद्र बोस), या, यदि इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाएं, तो अमर कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर – जिन्होंने अपने समकालीन जापानियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान किया था। वास्तव में, आधुनिक काल के प्रारंभ में जापान और भारत के बौद्धिक नेताओं द्वारा विचारों का जितना अधिक गहन और समृद्ध आदान–प्रदान किया गया, वह कुछ मायनों में ऐसा है जिसकी हम आधुनिक काल में केवल परिकल्पना ही कर सकते हैं।

इस समृद्ध इतिहास के बावजूद, मैं यह दृढ़ धारणा व्यक्त करना चाहूँगा कि भारत और जापान में आज जो परिवर्तन होने शुरू हो रहे हैं, वास्तव में उनकी कोई मिसाल नहीं है। सबसे पहले, हम हाल में भारत के प्रति जापानियों के बढ़ते आकर्षण और जापानी भाषा सीखने के लिए

भारतीयों में बढ़ती उत्सुकता के अलावा दोनों देशों में अन्य बातों में भी दिलचस्पी देख रहे हैं जो समाज के किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें आम जनता भी शामिल है।

निस्संदेह इसकी पृष्ठभूमि में हमारी बढ़ती अपेक्षाएं ही हैं जिनसे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और इसका स्पष्ट प्रमाण इसी बात से परिलक्षित होता है कि निप्पोन केईदानरेन के अध्यक्ष श्री फुजियो मितारई सहित लगभग 200 व्यावसायिक कार्यपालक मेरे साथ भारत की यात्रा पर आए हैं।

दूसरा, आम जापानी में भारत में दिलचस्पी लेने की जो भावना है, वह उसके माध्यम से इस विस्तृत एशिया की यथार्थता को जानने का प्रयास कर रहा है। जापान ने *भारत एक खोज* का अनुभव लिया है, जिससे मेरा अभिप्राय यह है कि हमने भारत की, एक प्रतिपक्ष के रूप में, पुनः खोज की है जो हमारे हितों और मूल्यों को समझता है तथा एक भागीदार के रूप में भविष्य में भी यह हमारे साथ स्वतंत्रता और समृद्धि के माहौल को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करेगा जो सभी के लिए खुला और पारदर्शी होगा।

मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या जापान के प्रति आपकी अवधारणा में भी इसी प्रकार का बदलाव आ रहा है? यदि किन्ही कारणों से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है तो क्या मैं यह मान सकता हूँ कि आज इसकी शुरुआत हो चुकी है?

* *

यहाँ मैं आपके साथ उन अनेक उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्हें भारत ने दुनिया को दिया है – और दुनिया को दे सकता है। मैं यह मानता हूँ कि इस तरह की सभा में भारत की उपलब्धियों पर बात करना थोड़ा अलग सा लग सकता है, लेकिन मैं

इस पर आपकी सहमति चाहूँगा, क्योंकि इसका संबंध उससे है जिस पर मैं इसके बाद अपने विचार व्यक्त करूंगा।

मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत दुनिया को जिन क्षेत्रों में योगदान दे सकता है उनमें से सर्वप्रथम इसकी सहिष्णुता की भावना है। यदि मैं 1893 में शिकागो में विवेकानंद द्वारा दिए गए गूढ़ अर्थपूर्ण भाषण के निष्कर्ष के एक अंश से निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा।

"Help and not Fight", "Assimilation and not destruction", "Harmony and Peace and not Dissension".
उन्होंने कहा था, "सहायता करो, संघर्ष नहीं," "आत्मसात करो, विनाश नहीं", "मैत्रीभाव एवं शांति रखो, मनमुटाव नहीं"।

आप इन संदेशों को आधुनिक काल के संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सहिष्णुता के ये उद्गार विगत का अवशेष न होकर वर्तमान के हैं। इसकी बजाय हम यह मान सकते हैं कि आज इनका भाव और महत्व पहले की तुलना में कहीं अधिक बाध्य करने वाला है।

जापान के लोग अशोक महान के शासनकाल से लेकर महात्मा गांधी जी के विरोध प्रदर्शित करने के अहिंसावादी *सत्याग्रह* आंदोलन तक, भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में सहिष्णुता से भली–भांति परिचित हैं।

आज मैं भारत के लोगों को यह बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि जापानी लोग भारत की जनता के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं ताकि सहिष्णुता की यह भावना इस सदी का प्रमुख सिद्धांत बन जाए।

मेरे विचार में, भारत का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान उसकी बृहत् प्रतिबद्धता है जिसका निर्वहन किया जा रहा है।

आंकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि 2050 तक, भारत दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्वानुमानों के अनुसार, यदि हम केवल 2030 तक की ही बात करें तो भारत में लगभग 270 मिलियन लोगों की नए सिरे से देहातों को छोड़कर, शहरों और नगरों में बसने की संभावना है।

मेरे विचार में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, गरीबी के खिलाफ संघर्ष करना है जो आज भी जारी है और लोकतांत्रिक तरीकों से उन सामाजिक समस्याओं से पार पाना है जो जनसंख्या में बदलाव का प्रतीक हों, ताकि आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त की जा सके।

एक व्यक्ति के रूप में, जिस पर राष्ट्र की दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी हो, आपकी आकांक्षाओं के कार्य–क्षेत्र तथा इनके कार्यान्वयन में आने वाली अनगिनत कठिनाइयों की वजह से मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। दुनिया ने अपना ध्यान आप पर केन्द्रित कर रखा है जो आपको इन चुनौतियों से निपटने का बीड़ा उठाते हुए देख रही है, और मैं भी बड़ी आशा से आपकी ओर देख रहा हूँ।

* *

जापान और भारत एक "नीतिगत वैश्विक भागीदारी" बनाकर अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं और उन्हें सुदृढ़ कर रहे हैं, और ऐसा करते हुए उनके उद्देश्य परस्पर एक बन गए हैं। जापान, इस तरह से, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। और मुझे आशा है कि मेरी आज की इस टिप्पणी से आप यह बात समझ गए होंगे कि जापान भारत से क्या प्रतिक्रिया चाहता है और उसकी क्या अपेक्षाएं हैं।

यह भागीदारिता एक ऐसा संबंध है जिसमें हम मूलभूत मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मूलभूत मानवाधिकारों का सम्मान करने के अतिरिक्त नीतिगत हितों का आदान–प्रदान करते हैं।

जापान की कूटनीति अब अनेक क्षेत्रों में विभिन्न अवधारणाओं को प्रोत्साहन दे रही है ताकि यूरेशियन महाद्वीप की बाहरी सीमा पर "स्वतंत्रता और समृद्धि की आर्क" नामक एक घेरा बन सके। जापान और भारत की नीतिगत वैश्विक भागीदारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि इस तरह से जापान और भारत एक–दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया को शामिल करके यह "विस्तृत एशिया" एक ऐसा विशाल नेटवर्क विकसित करेगा जो पूरे प्रशांत महासागर में फैल जाएगा। इस मुक्त और पारदर्शी नेटवर्क से लोगों को वस्तुओं, पूंजी और ज्ञान से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमारे दोनों देशों के लोकतंत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी वास्तव में क्षेत्र में स्वतंत्रता और समृद्धि को प्राप्त करना है ?

इसके अलावा, समुद्री सीमाओं वाले देशों के रूप में समुद्री मार्गों की सुरक्षा, भारत और जापान दोनों के महत्वपूर्ण हितों को प्रभावित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं जिन समुद्री मार्गों की बात कर रहा हूँ उनका आशय नौ–परिवहन से है जो विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आने वाले वर्षों में ऐसे देशों की ताकत को साथ मिलाकर इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कार्य करें जो हमें सौंपी गई है ?

अब प्रश्न यह उठता है कि जापान और भारत को आने वाले वर्षों में सुरक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सहयोग करना चाहिए। इनमें से एक

उपाय यह है कि हमारे देशों के कूटनीति और रक्षा के प्रभारी पदाधिकारियों को इस विषय पर संयुक्त रूप से विचार करना चाहिए। मैं इसे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष उनके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहूँगा।

* *

यदि आप मुझे एक मिनट के लिए विषय से हटकर कुछ बोलने की अनुमति दें तो मैं यह बात कहना चाहूँगा कि जापान के सरकारी विकास सहायता में भारत से जुड़े कुछ विषयों, विशेषकर वन और जल से संबंधित परियोजनाओं का बार–बार उल्लेख किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए त्रिपुरा, गुजरात और तमिलनाडु में जापानी सरकारी विकास सहायता लोगों को वनों में वृक्षों को काटे बिना जीवन यापन करनेद्व स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वनों का संरक्षण करने और उन्हें पुनः वनरोपण करने में सहायता कर रहे हैं। कर्नाटक में हमने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गहन वृक्षारोपण पहलों को कार्य रूप दिया है और ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनसे गरीबी दूर करने के लिए धनार्जन किया जा सके।

इसके अलावा, गंदे पानी के उपचार की सुविधाओं का निर्माण किया गया है और गंगा मैया को साफ करने के उपाय किए हैं, बंगलौर में जलापूर्ति और गंदे पानी के उपचार के लिए सुविधाएँ स्थापित की हैं, तथा हैदराबाद के बीचोबीच हुसैन सागर झील के पानी को साफ करने के लिए कार्रवाई की गई है, क्योंकि जापान की यह दृढ़ इच्छा रही है कि भारत को स्वच्छ जल मिले।

इन परियोजनाओं के माध्यम से आप यह जान जाएंगे कि जापानी लोगों को भारत से कितनी आशाएं हैं। जापानी लोगों के लिए उनके वन खज़ाने की तरह हैं और वे अपनी अथाह जलराशि का सम्मान करते हैं।

इसके अलावा, जापानियों को इस बात की भी जानकारी है कि भारत के लोग बहुत संवेदनशील हैं जिसकी वजह से वे प्रत्येक वृक्ष और घास की हरेक पत्ती को सजीव मानते हैं और सृष्टि के सभी जीवों को अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। जापानी और भारतीय, दोनों प्राकृतिक जगत के प्रति इतना अधिक श्रृद्धा का भाव रखते हैं कि यह मानना असंभव लगता है कि हमारे देशों के लोगों में कुछ बातें एकसमान नहीं हैं।

हम जापानी लोगों की यह दृढ़ इच्छा है कि भारतीय लोग अपने वनों का पोषण करेंगे और उन्हें फलने–फूलने देंगे तथा स्वच्छ जल का भरपूर मात्रा में उपयोग करेंगे। इसीलिए, सरकारी विकास सहायता के रूप में जापान से प्राप्त सहयोग में वन संरक्षण में सहायक बातें और वर्ष दर वर्ष जल की गुणवत्ता में सुधार करने वाली बातों को निरपवाद रूप से शामिल किया गया है।

कुछ समय पहले मैंने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए *"कूल अर्थ 50"* नामक एक पहल दुनिया के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस पहल के अंतर्गत 2050 तक ग्रीनहाउस गैसों की उत्सर्जन मात्रा में 50 प्रतिशत कमी की जाएगी।

मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपसे इस प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जापान और भारत 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा में 50 प्रतिशत की कमी करने के इस लक्ष्य को एकसाथ मिलकर हासिल करें।

क्योतो प्रोटोकोल के बाद जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण प्रणाली के लिए जिस आधारभूत ढांचे की परिकल्पना मैंने की है, उसमें सभी प्रमुख उत्सर्जक देश शामिल होंगे, और उस दृष्टि से इसे मौजूदा प्रोटोकोल से कहीं अधिक आगे बढ़ना होगा। प्रत्येक देश की परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह ढांचा लचीला और विविध होना चाहिए। इस ढांचे द्वारा

पर्यावरणीय सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य पैदा करने के लिए यथासंभव उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए।

मैं आपसे यानी भारत की जनता के प्रतिनिधियों से यह अपील कर रहा हूँ क्योंकि अन्य किसी देश के लोगों का प्रकृति के साथ इतना अधिक सद्भावनापूर्ण रिश्ता नहीं रहा है जो उनके पूरे इतिहास में दर्शनशास्त्र पर केन्द्रित रहा हो जितना कि भारत के लोगों का, और इसीलिए इस धरती पर ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जिसके लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करना इतना उपयुक्त बैठता हो।

मैं आपसे इस मार्ग पर चलने के लिए विचार करने का आग्रह करता हूँ, हालांकि इसमें कठिन चुनौतियॉ आएंगी, तथा आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के बीच संतुलन भी कायम करना होगा, किंतु यह ऐसा मार्ग है जिस पर हमें अवश्य चलना चाहिए। निस्संदेह जापान द्वारा दी जाने वाली सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है विशेषकर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

* *

जैसा कि मैंने कुछ देर पहले उल्लेख किया था कि इस यात्रा में मेरे साथ जापानी कंपनियों से लगभग 200 कार्यपालक आए हैं। वे इस समय भारत के अग्रणी व्यावसायियों के साथ एक मंच में विचार–विमर्श कर रहे हैं और हमारे दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं।

इसे देखते हुए मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं जापानी वार्ताकारों से जापान और भारत के बीच आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य करने के लिए आग्रह करूँ ताकि एक व्यापक और उचित प्रकार से तैयार समझौते का प्रारूप दुनिया के लिए एक

मिसाल कायम कर सके। इसी प्रकार, मैं भारतीय पक्ष से भी इस समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने में अपना समर्थन देने का अनुरोध करता हूँ।

भविष्य में, हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार में निवेश प्रभावशाली ढंग से बढ़ेगा। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अगले केवल तीन वर्षों में इस निवेश लगभग 20 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुल 2,800 किलोमीटर लंबे रेलवे कोरीडोर के माध्यम से मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में व्यापक उत्साह का परिचय दिया है। इन पर चलने वाली मालगाड़ियों की औसत गति 100 कि.मी. प्रति घण्टा होगी। दो महीनों के अंदर व्यवहार्यता अध्ययनों की अंतिम रिपोर्टें तैयार कर ली जाएगी। यह परियोजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जापान सक्रिय रूप से ऐसे उपायों पर विचार कर रहा है जिसके द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

इसके अलावा, जहॉ तक संभावित दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कोरीडोर का संबंध है, जिसे महत्वाकांक्षी मालभाड़ा कोरीडोर के साथ–साथ बनना है जापान और भारत फिलहाल इस पर विस्तृत विचार–विमर्श कर रहे हैं। विशेषकर इस कान्सेप्ट को रूप देने वाले कोष की स्थापना के लिए मैं सोचता हूँ कि मेरी सरकार भारतीय पक्ष के साथ घनिष्ठ सहयोग करे।

आज शाम मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलूँगा, और हम इसकी रूपरेखा पर विचार करेंगे जिसके द्वारा हम वह दिशा तय कर सकते हैं जिस पर चलकर जापान और भारत के बीच संबंध और सुदृढ़ हो सकेंगे। मैं समझता हूँ कि अपनी बातचीत के बाद हम इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में कोई घोषणा कर सकेंगे।

मैं आपको, यानी भारत के नागरिकों के प्रतिनिधियों को यह बताना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि "जापान–भारत संबंधों को दुनिया में कहीं भी किसी द्विपक्षीय संबंध को बनाने के लिए व्यापक क्षमता का वरदान हासिल है। हमारा पूरी तरह से यह मानना है कि एक सुदृढ़ भारत, जापान के हित में है और एक सुदृढ़ जापान, भारत के हित में है।

* *

अब चूंकि यह "विस्तृत एशिया" हिन्द और प्रशांत महासागरों के संगम का नया रूप ले रहा है, अतः मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है कि इन महासागरों के किनारे बसे लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों में प्रत्येक संभावित स्तर पर दोस्ती की भावना को और भी ज्यादा सुदृढ़ करें।

इसे ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि अगले पाँच वर्षों में हम जापान में प्रतिवर्ष 500 भारतीय युवाओं का स्वागत करेंगे। इनमें से लगभग 100 स्थान जापानी भाषा का अध्ययन करने और जापानी भाषा सिखाने वालों के लिए रखे जाएंगे, जो भावी पीढ़ियों के लिए एक निवेश साबित होगा।

इसके अतिरिक्त, दोनों देशों को लाभ पहुँचाने के अलावा यह इस नए "विस्तृत एशिया" के भविष्य में भी एक निवेश होगा। यह दुनिया में स्वतंत्रता और समृद्धि लाने के साथ–साथ विभिन्न लोगों के बीच "सह–अस्तित्व" लाने का एक प्रयास है जैसा कि विवेकानंद ने सिखाया था।

भारत और जापान के बीच संबंध कायम करने वाला यह मैत्रीभाव निश्चित रूप से हमारे दोनों देशों के लोगों का नेतृत्व करेगा जिससे दोनों एक–दूसरे की गहरी भावनाओं को समझ सकेंगे, जिसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

50 वर्ष पहले मेरे नाना नोबुसुके किशी भारत की यात्रा करने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री थे। तब प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू मेरे नानाजी को एक निजी "नागरिक स्वागत–समारोह" में ले गए थे जिसमें हज़ारों लोग एकत्र हुए थे। उन्होंने बड़े उत्साह से उपस्थित जनसमूह से उनका परिचय कराते हुए कहा था, "यह व्यक्ति जापान का प्रधान मंत्री है, एक ऐसा देश जिसका मैं बेहद सम्मान और आदर करता हूँ।" यह वह कहानी है जिसे मैंने बचपन में अपने नानाजी के चरणो में बैठकर सुना था। युद्ध में पराजित राष्ट्र के नेता के रूप में वह यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे।

किशी वे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जापान सरकार की युद्धोपरांत पहली सरकारी विकास सहायता शुरू की थी। तब जापान स्वयं एक गरीब देश था, लेकिन हम सम्मान के साथ सरकारी विकास सहायता उपलब्ध कराना चाहते थे। उस समय, जिस देश ने जापान का सरकारी विकास सहायता स्वीकार किया था, वह और कोई नहीं, भारत था। मेरे नानाजी इस बात को कभी भी नहीं भूले।

मैं जानता हूँ कि भारतीय संसद प्रत्येक वर्ष जापान पर गिराए गए बमों की तारीखों पर प्रार्थना सभा का आयोजन करती है। और पिछले कई वर्षों से जापान के बच्चों के लिए आपके देश से उपहार स्वरूप चार हाथी भेजे गए हैं।

प्रधान मंत्री नेहरू ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए जापान को एक हाथी भेंट किया था जिसका नाम उनकी पुत्री इन्दिरा के नाम पर था। तब से लेकर अब तक भारत सरकार ने जापान के चिडियाघर को तीन और हाथी दिए हैं, और इनमें से हरेक का नाम भूलना लगभग नामुमकिन है।

आशा, दया और सूर्या। सूर्या जापान में मई 2001 में आया था, जब जापान मंदी के दौर से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। सूर्या ने हमें स्मरण कराया कि जापान में सूर्य एक बार फिर उदय होगा!

इन सभी उपहारों के लिए मैं जापान की जनता की ओर से अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

* *

अंत में, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। जब जापानी भारत आते हैं तो आपकी नज़र में वे निरपवाद रूप से किस चीज़ में पारंगत होते हैं ?

वह है भारतीय नृत्य जैसे "भरत नाट्यम" और "कथक नृत्य शैली", जिसमें स्थिर और गतिशील का भेद सजीव और उत्कृष्ट होता है। इसमें नर्तकों और संगीतकारों के सुर–ताल की सूक्ष्म लयबद्धता अविश्वसनीय पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, मानो कि इसे इसी रूप में लिपिबद्ध किया गया हो। इसे देखकर कुछ कहते नहीं बनता, बस केवल यही सोचा जा सकता है कि यह बहुत ही जटिल गणना का परिणाम है।

भारत और जापान ऐसे ही भागीदार बनना चाहते हैं जो एक–दूसरे के साथ इसी तरह के सही तालमेल का प्रदर्शन करें। मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है।

आज आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

———